भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 168
सोमवार, 9 मार्च, 2026 (18 फाल्गुन 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में विमानपत्तनों का कम घनत्व

168 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 0.11 विमानपत्तन है, जबकि यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमरीका में 47.35 और चीन में 0.39 है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत है कि विमानपत्तनों की इतनी कम संख्या क्षेत्रीय संपर्क, हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि और संभार तंत्र दक्षता में बाधा डालती है;

(ग) इस अवसंरचनात्मक अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही नई विमानपत्तन परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विस्तारों और उनकी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में विमानपत्तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल सहित सार्वजनिक और निजी निवेश का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"देश में विमानपत्तनों का कम घनत्व" के संबंध में श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 09.03.2026 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 168 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): वर्तमान में देश में 164 परिचालनरत हवाईअड्डे हैं। भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते विमानन बाजारों में से एक है और वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। इस क्षेत्र में बढ़ती मांग और उत्पन्न होती चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

(i) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को जारी किया गया था जिसका उद्देश्य एयरलाइनों, हवाईअड्डों, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ), और उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) सहित सभी उप-क्षेत्रों को कवर करते हुए सामंजस्यपूर्ण तरीके से विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

(ii) सरकार ने आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए अक्टूबर, 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान योजना शुरू की है। आरसीएस-उड़ान योजना की शुरुआत के बाद से 95 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 663 मार्गों को चालू किया गया है। क्षेत्रीय संपर्क को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करते हुए देशभर में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित 'उड़ान' योजना की घोषणा की है।

(iii) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) ने देशभर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगि, ओर्वाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा, राजकोट (हीरासर) और नवी मुंबई में 13 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को प्रचालनरत किया गया है।

(iv) देश के सभी परिचालनरत हवाईअड्डों की कुल यात्री प्रबंधन क्षमता वर्ष 2014 में लगभग 200 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) से बढ़कर वर्तमान में 570 एमपीपीए से अधिक हो गई है।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर यात्री मांग पूर्वानुमानों, परिचालन अपेक्षाओं और एयरलाइनों से मांग, भूमि की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता, सांविधिक और विनियामक मंजूरी और अन्य साइट-विशिष्ट कारकों के आधार पर हवाईअड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, कार्य पूरा होने की समय-सीमा इन कारकों के आधार पर अलग-अलग होती है।

(घ): देश में हवाईअड्डे की क्षमता विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का लाभ ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों हवाईअड्डों के लिए उठाया जा रहा है। ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के मामले में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने आठ हवाईअड्डों

अर्थात् दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दीर्घकालिक आधार पर पट्टे पर दिया है। इन हवाईअड्डों के रियायतकर्ता प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (ओएमडीए) और रियायत समझौते, जैसा लागू हो, में निर्धारित प्रमुख योजना और विकास कार्यों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, एएआई के ग्यारह हवाईअड्डों, जिनमें पाँच प्रमुख हवाईअड्डे और छह छोटे हवाईअड्डे शामिल हैं, की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत उनके प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भी पहचान की गई है। इसके अलावा, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जैसे ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास भी पीपीपी मोड के माध्यम से किया जा रहा है।

देश में हवाईअड्डा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए, एएआई और पीपीपी भागीदारों ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 96000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है।

******